



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 4 जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 13, 1942 शक संवत्) [संख्या 26**

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	783—790	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	543—549	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	175—191	
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाँठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	315—336	975
			स्टोस—पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**नियुक्ति विभाग**

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

13 मई, 2020 ई०

सं० 684/दो-1-2020-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 मई, 2020 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1—श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, आई०ए०एस० (एस०सी०एस-2005)

2—डा० राम मनोहर मिश्रा, आई०ए०एस० (एस०सी०एस-2009)

आज्ञा से,  
धनन्जय शुक्ला,  
विशेष सचिव।

**राज्य कर विभाग**

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

27 मई, 2020 ई०

सं० राज्य कर-1-346/11-2020-160/2016—कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या स्था०-1-पी०एफ०—श्रीमती सरिता सिंह, ज्वा० कमि०/04/वाणिज्य कर, दिनांक 08 मई, 2020 के माध्यम से प्राप्त श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर बांदा सम्भाग, बांदा के अनुरोध पत्र के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर बांदा सम्भाग बांदा का गृह जनपद एतद्द्वारा परिवर्तित किया जाता है—

नाम	पदनाम	गृह जनपद	परिवर्तित गृह जनपद
श्रीमती सरिता सिंह	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर बांदा सम्भाग, बांदा	उन्नाव (उ०प्र०)	गुरुग्राम (हरियाणा)

2—उपरोक्त गृह जनपद परिवर्तन इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह गृह जनपद परिवर्तन उक्त अधिकारी के सेवाकाल में अन्तिम होगा।

प्रोन्नति

01 जून, 2020 ई०

सं० राज्य कर-1-375/11-2020-107/2019—वाणिज्य कर विभाग के श्री राजेश सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-1370), ज्वाइन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर (वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 8,700) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव।

## विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान अनुभाग]

सेवा-निवृत्ति

01 जून, 2020 ई०

सं० 460/वि०स०/अधि०/04/87—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत श्रीमती मुन्नी देवी, विशेष सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, दिनांक 05 मई, 2020 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने के उपरान्त दिनांक 31 मई, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गयी।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

## गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

प्रोन्नति

30 मई, 2020 ई०

सं० 213डीजी/छ:पु०से०-2-2020-522(105)/2019—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) के अधिकारी श्री सफी एहसन रिजवी, आरआर-1989, श्री आशीष गुप्ता, आरआर-1989 एवं श्री आदित्य मिश्र, आरआर-1989 जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को पुलिस महानिदेशक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु० 2,05,400-2,24,400) तालिका के कालम 5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र०	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	कब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं	राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनके सापेक्ष अपर पुलिस महानिदेशक के वेतनमान (पे-मैट्रिक्स लेवल-16 रु० 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया जाना है	स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—			सर्वश्री—	
1	सफी एहसन, (यूकेडी)	आरआर-1989	18-01-2006	चन्द्र प्रकाश, आरआर-1989	01-04-2020 पूर्वान्ह
2	आशीष गुप्ता	आरआर-1989	23-09-2014	चन्द्र प्रकाश, आरआर-1989	01-04-2020 पूर्वान्ह
3	आदित्य मिश्र	आरआर-1989	02-12-2019	चन्द्र प्रकाश, आरआर-1989	01-04-2020 पूर्वान्ह

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

**परिवहन विभाग**

अनुभाग-3

पदोन्नति

29 मई, 2020 ई0

सं0 31/2020/1358/30-3-2020-70जीई/2017-कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री संजीव कुमार गुप्ता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैंड-4, रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600 (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री संजीव कुमार गुप्ता की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव।

**नियोजन विभाग**

अनुभाग-1

नियुक्ति

20 मार्च, 2020 ई0

सं0 117/35-1-2020-6/8 (4)/99 टी0सी0-III-प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 कालाकांकर भवन, लखनऊ के अन्तर्गत उप निदेशक के 01 (उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिये आरक्षित) पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु किये गये चयन तथा "आयोग" की संस्तुति के आधार पर श्री राम धीरज को उप निदेशक के सीधी भर्ती के पद पर पे बैंड रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,  
कुमार कमलेश,  
अपर मुख्य सचिव।

**भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग**

नियुक्ति

06 मई, 2020 ई0

सं0 721(1)/86-2020-165/14टी0सी0-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक भू-भौतिकविद् पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी श्री दीपेन्द्र यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव, ग्रा0-हरदी, पो0-जमुई पण्डित, जिला महाराजगंज, उ0प्र0-273207, रजिस्ट्रेशन संख्या 53100076701 को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाया गया है।

2-अतएव उक्त चयनित अभ्यर्थी श्री दीपेन्द्र यादव को श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत वेतन बैंड रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 में सहायक भू-भौतिकविद् के पद पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में तैनात किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं-

1-उक्त अभ्यर्थी श्री दीपेन्द्र यादव, सहायक भू-भौतिकविद् के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—इनकी सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गयी संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होगी।

3—इनको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो, दे होंगे।

4—उ0प्र0 अस्थायी स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

5—श्री दीपेन्द्र यादव अपनी योगदान आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6—श्री दीपेन्द्र यादव एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7—तैनाती के जनपद तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8—उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

9—इन सहायक भू-भौतिकविद् की पारस्परिक ज्येष्ठता उ0प्र0, सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

27 मई, 2020 ई0

सं0 688(1)/86-2020-13(बजट)/17—भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या 309(1)/86-2018-183/2011, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से उ0प्र0, खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 की 1500 प्रतियां हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित कराये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 07 मई, 2019 द्वारा बिल बीजक संख्या 131/2019, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 की धनराशि रु0 18,977.00 (रु0 अट्ठारह हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या 1909(1)/86-2019, दिनांक 14 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु संगत मद में बजट आवंटन नहीं होने से उक्त बिल का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 निरस्त करते हुये उक्त रुपये 18,977.00 का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये जाने हेतु स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 78 के लेखाशीर्षक—“3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें—090—सचिवालय—03—सचिवालय—18 प्रकाशन एवं फार्मों की छपाई” के नामे डाला जायेगा तथा उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक—“0058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण लघु शीर्षक—03 दूसरे सरकारी विभागों के लिये किया गया मुद्रण कार्य” में जमा की जायेगी।

सं0 688(3)/86-2020-13(बजट)/17—भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या 327/86-2019, दिनांक 12 फरवरी, 2019 द्वारा राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक की 1300 प्रतियां हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित कराये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 15 मई, 2019 द्वारा बिल बीजक संख्या 203/2019, दिनांक 09 मई, 2019 की धनराशि

रु0 28,143.00 (रु0 अट्ठाइस हजार एक सौ तैतालिस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या 1909(3)/86-2019, दिनांक 14 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु संगत मद में बजट आवंटन नहीं होने से उक्त बिल का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 निरस्त करते हुये उक्त रुपये 28,143.00 का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये जाने हेतु स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 78 के लेखाशीर्षक-“3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-090-सचिवालय-03-सचिवालय-18 प्रकाशन एवं फार्मों की छपाई” के नामे डाला जायेगा तथा उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक-“0058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण लघु शीर्षक-03 दूसरे सरकारी विभागों के लिये किया गया मुद्रण कार्य” में जमा की जायेगी।

सं0 688(5)/86-2020-13(बजट)/17-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या 1868(1)/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से उ0प्र0, उपखनिज (परिहार) नियमावली (सैतालिसवां संशोधन) की 1500 प्रतियां हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित कराये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 05 मार्च, 2020 द्वारा बिल बीजक संख्या 1219/19, दिनांक 22 फरवरी, 2020 की धनराशि रु0 50,991.00 (रु0 पचास हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 78 के लेखाशीर्षक-“3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-090-सचिवालय-03-सचिवालय-18 प्रकाशन एवं फार्मों की छपाई” के नामे डाला जायेगा तथा उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक-“0058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण लघु शीर्षक-03 दूसरे सरकारी विभागों के लिये किया गया मुद्रण कार्य” में जमा की जायेगी।

आज्ञा से,  
डा0 रोशन जैकब,  
सचिव।

## होमगार्ड्स विभाग

नियुक्ति

09 जून, 2020 ई0

सं0 26/2020/1047/पन्चानवे-2020-71 होगा/16पार्ट-II-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परीक्षाफल के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री नीरज कुमार शर्मा को श्री राज्यपाल महोदय पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में जिला कमाण्डेंट, होमगार्ड्स संवर्ग के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री नीरज कुमार शर्मा होमगार्ड्स संगठन में अपने योगदान की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने जायेंगे और परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

3-जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स का पद होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) के वेतनक्रम में अन्य पदों के साथ मिले जुले संवर्ग में है। अतः इस पदधारक को न केवल एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया जा सकता है, वरन होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत उसी वेतनक्रम में अन्य पदों पर भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है।

4-श्री नीरज कुमार शर्मा को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य की गयी दरों पर वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5-होमगार्ड्स संगठन में कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री नीरज कुमार शर्मा को कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6—श्री नीरज कुमार शर्मा की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

7—श्री नीरज कुमार शर्मा एक सप्ताह के अन्दर कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

8—कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ श्री नीरज कुमार शर्मा के प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि में उनके वेतन भत्तों आदि के आहरण एवं वितरण की भी व्यवस्था करेंगे तथा प्रशिक्षणोपरान्त तैनाती का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 27/2020/1048/पन्चानवे-2020-71 होगा/16पार्ट-II—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परीक्षाफल के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री सुधाकर शरण पाण्डेय को श्री राज्यपाल महोदय पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स संवर्ग के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री सुधाकर शरण पाण्डेय, होमगार्ड्स संगठन में अपने योगदान की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने जायेंगे और परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

3—जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स का पद होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) के वेतनक्रम में अन्य पदों के साथ मिले जुले संवर्ग में हैं। अतः इस पदधारक को न केवल एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया जा सकता है, वरन् होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत उसी वेतनक्रम में अन्य पदों पर भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है।

4—श्री सुधाकर शरण पाण्डेय को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य की गयी दरों पर वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5—होमगार्ड्स संगठन में कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री सुधाकर शरण पाण्डेय को कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6—श्री सुधाकर शरण पाण्डेय की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

7—श्री सुधाकर शरण पाण्डेय एक सप्ताह के अन्दर कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

8—कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ श्री सुधाकर शरण पाण्डेय के प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि में उनके वेतन भत्तों आदि के आहरण एवं वितरण की भी व्यवस्था करेंगे तथा प्रशिक्षणोपरान्त तैनाती का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 28/2020/1049/पन्चानवे-2020-71 होगा/16पार्ट-II—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परीक्षाफल के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री हरि शंकर चौधरी को श्री राज्यपाल महोदय पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स संवर्ग के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री हरि शंकर चौधरी, होमगार्ड्स संगठन में अपने योगदान की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने जायेंगे और परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

3—जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स का पद होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) के वेतनक्रम में अन्य पदों के साथ मिले जुले संवर्ग में हैं। अतः इस पदधारक को न केवल एक जिले से दूसरे

जिले में स्थानान्तरित किया जा सकता है, वरन होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत उसी वेतनक्रम में अन्य पदों पर भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है।

4—श्री हरि शंकर चौधरी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य की गयी दरों पर वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5—होमगार्ड्स संगठन में कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री हरि शंकर चौधरी को कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6—श्री हरि शंकर चौधरी की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

7—श्री हरि शंकर चौधरी एक सप्ताह के अन्दर कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

8—कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ श्री हरि शंकर चौधरी के प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि में उनके वेतन भत्तों आदि के आहरण एवं वितरण की भी व्यवस्था करेंगे तथा प्रशिक्षणोपरान्त तैनाती का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 29/2020/1050/पन्चानवे-2020-71 होगा/16पार्ट-II—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परीक्षाफल के आधार पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री शैलजा एन सिंह को श्री राज्यपाल महोदय पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स संवर्ग के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—सुश्री शैलजा एन सिंह, होमगार्ड्स संगठन में अपने योगदान की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने जायेंगे और परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

3—जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स का पद होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) के वेतनक्रम में अन्य पदों के साथ मिले जुले संवर्ग में है। अतः इस पदधारक को न केवल एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया जा सकता है, वरन होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत उसी वेतनक्रम में अन्य पदों पर भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है।

4— सुश्री शैलजा एन सिंह को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य की गयी दरों पर वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5—होमगार्ड्स संगठन में कार्यभार ग्रहण करने हेतु सुश्री शैलजा एन सिंह को कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6—सुश्री शैलजा एन सिंह की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

7—सुश्री शैलजा एन सिंह एक सप्ताह के अन्दर कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

8—कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सुश्री शैलजा एन सिंह के प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि में उनके वेतन भत्तों आदि के आहरण एवं वितरण की भी व्यवस्था करेंगे तथा प्रशिक्षणोपरान्त तैनाती का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,  
अनिल कुमार,  
प्रमुख सचिव।





# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, ४ जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 13, 1942 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### बांदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

02 जून, 2020 ई०

सं० 93(6)/12-भूमि व्यवस्था-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र०अधि० संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम मटौंध ग्रामीण तहसील बांदा, जिला बांदा के श्रेणी-5-1 नवीन परती भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 419 रकबा 0.3840 हे०, जिसकी मालियत 2,76,480 रुपये (दो लाख छिहत्तर हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र) को ग्राम सभा मटौंध ग्रामीण में जनपद बांदा के मुकदमी वाहनों के प्रबन्धन हेतु उप जिलाधिकारी बांदा की संस्तुति/आख्या पत्र संख्या 1555/रा०नि०आ०, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की आख्या 04 नवम्बर, 2019 के अन्तर्गत थाना मटौंध के मुकदमी वाहनों के प्रबन्धन हेतु जिलाधिकारी, बांदा द्वारा पूर्व निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 04 नवम्बर, 2019 को वापस लेते हुये पुलिस अधीक्षक बांदा के पत्र संख्या भ-163/2019, दिनांक 19 मई, 2020 के क्रम में प्राप्त उप जिलाधिकारी, बांदा की संस्तुति आख्या पत्र संख्या 2022/रा०नि०आ०, दिनांक 31 मई, 2020 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) बांदा की आख्या दिनांक 01 जून, 2020 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त गांव सभा की भूमि जनपद बांदा के समस्त मुकदमी वाहनों के प्रबन्धन हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण

रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	बांदा	बांदा	मटौंध ग्रामीण	मटौंध ग्रामीण	5-1 नवीन परती, खाता संख्या 2958	419	0.3840	जनपद बांदा के समस्त मुकदमी वाहनों के प्रबन्धन हेतु।

03 मार्च, 2020 ई०

सं० 07(6)/12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र०अधि० संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम अनथुवा, तहसील अतर्रा, जिला बांदा, के श्रेणी-5-3-ड बंजर भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 980, रकबा 0.100 हे०, जिसकी मालियत 1,10,000 रुपये (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) को ग्राम सभा अनथुवा, ग्राम अनथुवा में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नवीन भवन निर्माण हेतु उप जिलाधिकारी अतर्रा की संस्तुति/आख्या, पत्र संख्या 1188/आ०आई० आफिस, दिनांक 12 मार्च, 2020 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की आख्या दिनांक 18 मार्च, 2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	बांदा	अतर्रा	अनथुवा	अनथुवा	5-3-ड बंजर, खाता संख्या 3038	980	0.100	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नवीन भवन निर्माण हेतु।

03 जून, 2020 ई०

सं० 98(6)/12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र०अधि० संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम गोयरा मुगली, तहसील बांदा, जिला बांदा, के श्रेणी-5-3-ड बंजर भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 960, रकबा 3.0364 हे०, जिसकी मालियत 21,25,480.00 रुपये (इक्कीस लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को ग्राम सभा गोयरा मुगली में संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन, बांदा प्रतिस्थापित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, बांदा की

संस्तुति/आख्या पत्र संख्या 1913/रा०नि०आ०, दिनांक 22 फरवरी, 2020 एवं जिला शासकीय अधिवक्त (राजस्व) की आख्या दिनांक 13 मार्च, 2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्गृहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्गृहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्गृहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील/परगना	ग्राम सभा	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बांदा	बांदा	गोयरा मुगली	गोयरा मुगली	5-3-ड बंजर, खाता संख्या 809	960-ख मि०	3.0364	संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन, सारथी हाल, आटोमैटिक ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक, फिटेश पिट निर्माण हेतु।

अमित सिंह बंसल,  
जिलाधिकारी, बांदा।

### कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

20 फरवरी, 2020 ई०

सं० 598व्यघ/०9 व्यघ/2019—लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सि०/प्रा०) जिन्हें, प्रथम वैयक्तिक वेतनमान अथवा द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रु० 5,400 प्राप्त हो रहा है, को कार्मि विभाग की राजाज्ञा संख्या 2150/कार्मिक-4-15ई०एम०/85, दिनांक 26 मई, 1986, राजाज्ञा संख्या 1661/47-4-44ई०एफ०/65, दिनांक 11 मार्च, 1991 एवं शासनादेश संख्या वे०आ०-2-796(1)/दस-62(एम) 2008 टी०सी०, दिनांक 31 मई, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं इनके सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, परिवार (क) वर्ग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। इन आदेशों के फलस्वरूप नामांकित अवर अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा—

### अनुसूची

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम	संवर्ग	विभाग में योगदान की तिथि	सहायक अभियन्ता का वेतनमान ग्रेड, वेतन रु० 5,400 प्राप्त करने की तिथि	तैनाती खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
1	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री मुलीधर	सिविल	18-08-2001	18-08-2017	प्रा०ख०, अमेठी
2	संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री केन्द्रपाल सिंह	सिविल	20-08-2001	20-08-2017	प्रा०ख०, एटा

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री-				
3	अरूण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राधारमण श्रीवास्तव	सिविल	16-08-2001	16-08-2017	नि0खं0-1, प्रयागराज
4	पशुपति नाथ त्रिपाठी पुत्र श्री दयानन्द त्रिपाठी	सिविल	17-08-2001	17-08-2017	नि0खं0-1, प्रयागराज
5	रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल चन्द्र यादव	सिविल	29-09-2001	29-09-2017	नि0खं0, प्रयागराज
6	राजेश कुमार निम पुत्र श्री हरिराम निम	सिविल	05-09-2001	05-09-2017	नि0खं0-3, (प्र0प0) गाजियाबाद
7	सतेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री प्रेमपाल	सिविल	16-05-2002	16-05-2018	नि0खं0-3 (प्र0प0), गाजियाबाद
8	अनुरुद्ध कुमार पुत्र श्री गंगादीन	सिविल	10-09-2001	10-09-2017	नि0खं0-3 (प्र0प0), गाजियाबाद
9	दयाशंकर कुशवाहा पुत्र श्री राम आशीष कुशवाहा	सिविल	08-09-2001	08-09-2017	नि0खं0 (भवन) गोरखपुर
10	संदीप त्यागी पुत्र श्री अशोक कुमार त्यागी	सिविल	16-08-2001	16-08-2017	नि0खं0, बागपत
11	अनूप कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा	सिविल	14-08-2001	14-08-2017	नि0खं0-2, अयोध्या
12	धनीराम भार्गव पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद	सिविल	05-09-2001	05-09-2017	प्रा0खं0, सीतापुर
13	बीरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री पृथ्वीपाल सिंह	सिविल	16-08-2001	16-08-2017	प्रा0 खं0, गोरखपुर
14	अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश गुप्ता	सिविल	04-09-2001	04-09-2017	प्रा0खं0, उन्नाव
15	जयविन्द कुमार पुत्र स्व0 नाथूराम	सिविल	14-08-2001	14-08-2017	प्रा0खं0, उन्नाव
16	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद सिंह	सिविल	16-08-2001	16-08-2017	नि0खं0-1, बाराबंकी
17	रामलाल सिंह पुत्र श्री रामसुन्दर सिंह	सिविल	20-08-2001	20-08-2017	नि0खं0-1, बाराबंकी
18	रघुराज सिंह पुत्र श्री जय सिंह	सिविल	19-04-2003	19-04-2019	नि0खं0, (भवन), बरेली
19	हृदय नारायण मिश्र पुत्र श्री राधारमन मिश्र	सिविल	03-01-2003	30-01-2019	प्रा0खं0, शाहजहांपुर
20	जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री पुत्तूलाल	सिविल	27-08-2001	27-08-2017	प्रा0खं0, कन्नौज
21	चन्द्रभूषण शर्मा पुत्र श्री सोमदत्त शर्मा	सिविल	31-08-2001	31-08-2017	नि0खं0-3, वाराणसी
22	श्याम जी श्रीवास्तव पुत्र श्रीनाथ सहाय श्रीवास्तव	सिविल	14-08-2001	14-08-2017	अनु0खं0-1 (सिविल), लखनऊ
23	वेद प्रकाश पुत्र श्री सरदार मौजी लाल वर्मा	सिविल	16-08-2001	16-08-2017	अनु0खं0-1 (सिविल), लखनऊ
24	अशोक कुमार पुत्र श्री राजकुमार	प्राविधिक	15-07-1996	15-07-2012	प्रा0खं0, कानपुर नगर

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
25	रमेश कुमार पाल पुत्र श्री संतपाल	सिविल	18-08-2001	18-08-2017	नि०खं०-1, लखीमपुर खीरी
26	राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बहोरी लाल गुप्ता	सिविल	01-09-2001	01-09-2017	अ०ख० (प्र०प०) गौतमबुद्ध नगर
27	ओम प्रकाश पुत्र स्व० जवाहर लाल	सिविल	01-09-2001	01-09-2017	प्रा०खं०, लखनऊ
28	राजकुमार सिंह पुत्र श्री किशनलाल	सिविल	01-05-2002	01-05-2018	प्रा०खं०, बागपत
29	मनवीर सिंह पुत्र श्री हरीराम	सिविल	29-08-2001	29-08-2017	नि०खं०-1, एटा
30	योगेश चन्द्र वर्मा पुत्र श्री रामभरोस लाल	सिविल	17-08-2001	17-08-2017	नि०खं०, अमरोहा
31	कमल कुमार पुत्र श्री रामशंकर	सिविल	13-05-2001	13-05-2018	प्रा०ख०, शाहजहांपुर
32	अवध नारायण पुत्र स्व० बाबूराम	सिविल	07-09-2001	07-09-2017	प्रा०ख०, औरैया
33	राजेश कुमार अग्निहोत्री पुत्र श्री रामकृष्ण अग्निहोत्री	सिविल	27-08-1992	27-08-2008	नि०ख०, औरैया
34	विनोद कुमार पुत्र श्री गौरीशंकर	सिविल	21-08-2001	21-08-2017	नि०ख० औरैया
35	चन्द्रशेखर सम्यक पुत्र श्री रामगोपाल	सिविल	04-08-2003	04-08-2019	प्रा०ख०, अलीगढ़
36	राकेश कुमार यादव पुत्र श्री राजन लाल	सिविल	08-04-2003	08-04-2019	प्रा०ख०, अलीगढ़
37	रमेश चन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल	सिविल	16-04-2003	16-04-2019	प्रा०ख०, अलीगढ़
38	सुनील कुमार पुत्र श्री राजदेव	सिविल	03-01-2003	03-01-2019	प्रा०ख०, सीतापुर
39	ताजवर हसन पुत्र स्व० श्री इब्ने हसन	सिविल	22-05-2002	22-05-2018	नि०खं०, अमरोहा
40	ओमकार सिंह पुत्र स्व० यशपाल सिंह	सिविल	16-08-2001	16-08-2017	नि०खं०-1, मुरादाबाद
41	बलिराम प्रसाद पुत्र श्री	सिविल	27-09-2001	27-09-2017	प्रा०ख०, जौनपुर
42	दिनेश सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र सिंह	सिविल	27-08-2001	27-08-2017	नि०खं०, सोनभद्र
43	नन्द लाल राम पुत्र श्री बसन्त राम	सिविल	07-09-2001	07-09-2017	नि०खं०, सोनभद्र
44	सुल्तान सिंह पुत्र श्री रामजीत सिंह	सिविल	04-09-2001	04-09-2017	नि०खं०-1, (ता०ट्रेप०) आगरा

राजपाल सिंह,  
प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०),  
लो०नि०वि०, लखनऊ।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)  
/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद चित्रकूट

17 जून, 2020 ई०

सं० 487/अधि०/स०सु०/2020—चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की

सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों के उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, चित्रकूट जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है—

### अनुसूची

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक जहां गति निबंधित रहेगी)	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू-व्हीलर/थ्री-व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	बांदा—लालता रोड	लमियारी से लालता रोड	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
2	कर्वी—मानिकपुर	कालूपुर से मानिकपुर	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
3	मानिकपुर—इटवां मारकुण्डी	मानिकपुर से इटवां वाया मारकुण्डी	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
4	कर्वी—ददरी	सोनेपुर से ददरी, वाया देवांगना मर्डइयन	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
5	मऊ—पूरब पताई	शिवपुर—पूरबपताई	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
6	पहाड़ी—देवल	पहाड़ी—देवल	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
7	कमासिन—सीतापुर	साईपुर—सीतापुर वाया शिवरामपुर	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा

1	2	3	4	5	6	7
8	राजापुर-सरैया	राजापुर से सरैया वाया बोडी पोखरी	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
9	राजापुर-कर्वी पहाड़ी	वाया बनकट मोड (कर्वी) से राजापुर (विद्युत सब स्टेशन) वाया पहाड़ी	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
10	कर्वी-राजापुर (विद्युत सब स्टेशन) वाया बूढ़ा नांदिन	कसहाई से राजापुर (विद्युत सब स्टेशन) वाया बूढ़ा सेमरवार	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
11	डढ़ियन फतेहगंज- चित्रकूट (वाया भारतपुर कोल्हौवा)	कोल्हौवा से सीतापुर वाया (भागवतपुर-भरतकूप मन्दिर-शिवरामपुर)	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—

[क] अग्नि शमन वाहन।

[ख] एम्बुलेंस।

[ग] पुलिस वाहन।

[घ] कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

[ङ] प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के कालम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेंगी।

प्रदीप कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी/जनपद-चित्रकूट।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, ४ जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 13, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली तारीख : 23 अप्रैल, 2020 ई०  
3 वैशाख, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-वि०स०/12 व 13/2017(इला०)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 2017, की निर्वाचन अर्जी संख्या 12 व 13 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तारीख 3 मार्च, 2020 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,  
अनुज जयपुरियार,  
वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

23<sup>rd</sup> April, 2020  
New Delhi dated the :  
Vaisakha 3, 1942 (Saka).

**No. 82/UP-LA/12 & 13/2017(Alld.)**—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 3<sup>rd</sup> March, 2020 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition no. 12 & 13 of 2017.



**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD****Election Petition No. 12 & 13 of 2017**

**Case :** Election Petition No. 12 of 2017.

**Petitioner :** Prempal Singh.

**Respondent :** Satya Pal Singh Baghel And 10 Others.

**Counsel for Petitioner :** In Person, Prempal Singh, Rakesh Kumar Gupta.

**Counsel for Respondent :** Sushil Kumar Srivastava.

Connected with-

**Case :** Election Petition No. 13 of 2017.

**Petitioner :** Rakesh Babu.

**Respondent :** Satya Pal Singh Baghel And 9 Others.

**Counsel for Petitioner :** In Person, Rakesh Babu, Rakesh Kumar Gupta.

**Counsel for Respondent :** Rakesh Kumar Gupta, Sanjay Kumar Srivastav,  
Sushil Kumar Srivastava.

**Hon'ble, Mahesh Chandra Tripathi, J.**

Order on Civil Misc. Application no. 19 of 2019 filed in Election Petition no. 12 of 2017 and Civil Misc. Application no. 17 of 2019 filed in Election Petition no. 13 of 2017 under Section 151 of Code of Civil Procedure on behalf of Satya Pal Singh Baghel respondent no. 1.

1. Both the aforesaid applications are filed to dismiss the Election Petition Nos. 12 of 2017 filed by Prempal Singh and 13 of 2017 filed by Rakesh Babu, as infructuous.

2. The facts giving rise to the election petitions may be briefly stated as follows: There were general elections to the U.P. Legislative Assembly in February, 2017. The last date for filing nomination papers was fixed on 24<sup>th</sup> January, 2017 and or before that date the petitioner Rakesh Babu in Election Petition no. 13 of 2017 and the respondent no. 1 Satya Pal Singh Baghel filed their nomination papers for Tundla Assembly Constituency (reserved for Scheduled Caste). The polling took place on 11<sup>th</sup> February, 2017 and the result was declared on 11<sup>st</sup> March, 2017 in which the respondent no. 1. was declared as elected. The petitioner Prem Pal Singh in Election Petition no. 12 of 2017 was an elector in the said constituency. The petitioners filed the election petitions questioning the validity of the election of the respondent no. 1 to the Tundla Assembly Constituency on the ground that the Tundla Constituency no. 95 was reserved for the Scheduled Caste. The respondent no. 1 is originally resident of District Auraiya, Uttar Pradesh and he belongs to Gaderia (Pal/Baghel) caste, which is recognized as 'Other Backward Caste' in the State of Uttar Pradesh. A prayer was, therefore, made to declare the election of the respondents no. 1 as void and for issuing appropriate consequential directions.

3. The written statement was filed on behalf of respondent no. 1 on 15-04-2018, denying the allegations levelled by the petitioners in the aforesaid election petitions. The petitioners filed replication dated 27-07-2018 in reply to written statement stating therein that the respondent no. 1 was not eligible to contest the election for Tundla Constituency no. 95 (reserved for Scheduled Caste) as he belongs to Gadaria caste, which is notified as 'Other Backward Classes' in the State of UP. He was also the National President of Bhartiya Janta Party Backward Caste Prakoshth and was working as Associate Professor in Agra College, Agra. Various other grounds have been taken in the affidavit filed in support of the replication. The objection with regard to replication has been preferred by the respondent no. 1 on 17-12-2018 for striking

out the paragraphs Nos. 4 to 86 of the replication or reject the replication with regard to the paragraph Nos. 4 to 86 and the documents filed in support of thereof in the replication.

4. After hearing both the parties the Court had proceeded to allow the objection filed on behalf of the respondent no. 1 on 27-02-2019 and rejected the replication dated 23-01-2019, insofar as it relates to paras 4 to 86, and the application under Order VII Rule 14 CPC preferred by the petitioners. The operative portion of the order dated 27-02-2019 reads as under :

“18. A perusal of the averments made in the election petition goes to show that the Election Petition of only seven paragraph was preferred by the petitioner on 25-04-2017 challenging the election of the first respondent to the U.P. Legislative Assembly from 95 Tundla Assembly Constituency in which the notice was issued to the first respondent on 26-05-2017. Finally the respondent filed his written statement on 23-04-2018 stating that the allegations contained in the election petitions are not supported by any material particulars inasmuch as vague and frivolous averment have been made in the Election Petition. The Petitioner has not alleged about the material effect on the result of the election in question and the pleadings are thus liable to be struck off from the election petition under the provisions of Order VI Rule 16 of Code of Civil Procedure. The petitioner does not disclose the cause of action, as such the election petition is liable to be dismissed by this Court.

19. Thereafter, the present replication in reply to the written statement containing 86 paragraphs was filed on 27-07-2018. Once an objection/application to the replication has been preferred by the first respondent on 17-12-2018 for rejecting the replication with regard to paragraph nos. 4 to 86 of the replication and new documents filed in support thereof, then the petitioner has filed an application under Order VII Rule 14 of Code of Civil Procedure in the Election Petition on 31-01-2019 asking leave of the Court. The request has been made to allow the application in question and consider all the evidences as a part of pleadings, which have annexed in the replication filed in reply to written statement filed by the first respondent. Through the replication in question, additional facts alongwith evidences have been brought on record much beyond the statutory period of limitation without leave of the Court, as such the objection so raised by Shri Shashi Nandan, Senior Advocate appearing on behalf of the first respondent definitely has force and his objection application is liable to be allowed.

20. It is settled law that election petition proceedings are technical and special proceedings. The Supreme Court of India has explained the legal position in that regard in paragraph-8 of its judgment in the case of Ram Sukh (supra), which reads as follows:

“8. Before examining the merits of the issues raised on behalf of the election petitioner with reference to the relevant statutory provisions, it would be appropriate to bear in mind the observations of this Court in *Jagan Nath V. Jaswant Singh*. Speaking for the Constitution Bench, Mehr Chand Mahajan, C.J., had said that the statutory requirement of election law must be strictly observed and that the election contest is not an action at law or a suit in equity, but is purely a statutory proceeding unknown to the common law and that the Court possesses no common law power. It is also well settled that the success of a candidate who has won at an election should not be lightly interfered with and any petition seeking such interference must strictly conform to the requirements of the law. Never the less, it is also to be borne in mind that one of the essentials of the election law is to safeguard the purity of the election process and, therefore, the courts must zealously ensure that people do not get elected by flagrant breaches of that law or by indulging in corrupt practices, as enumerated in the Act.”

21. In *Dhartipakar Madan Lal Agarwal* case (Supra) Hon'ble Supreme Court observed in paragraph-14 as under :

“Before we consider various paragraphs of the election petition to determine the correctness of the High Court order we think it necessary to bear in mind the nature of the right to elect, the right to be elected and the right to dispute election and the trial of the election petition. Right to contest election or to question the election by means of an election petition is neither common law nor fundamental right instead it is a statutory right regulated by the statutory provisions of the Representation of the People Act, 1951. There is no fundamental or common law right in these matters. This is well settled by catena of decisions of this Court in *N.P. Ponnuswami Vs. Returning Officer*, (1952) 1 SCR 218, *Jagan Nath v. Jawant Singh*, AIR 1954 SC 210 and *Jyoti Basu v. Debi Ghosal*, (1982) 3 SCR 318. These decisions have settled the legal position that outside the statutory provisions there is no right to dispute an election. The Representation of the People Act is a complete and self contained code within which any rights claimed in relation to an election or an election dispute must be found. The provisions of the Civil Procedure Code are applicable to the extent as permissible by Section 87 of the Act. The scheme of the Act as noticed earlier would show that an election can be questioned under the statute as provided by Section 80 on the grounds as contained in Section 100 of the Act. Section 83 lays down a mandatory provision in providing that an election petition shall contain a concise statement of material facts and set forth full particulars of corrupt practice. The pleadings are regulated by Section 83 and it makes it obligatory on the election petitioner to give the requisite facts, details and particulars of each corrupt practice with exactitude. If the election petition fails to make out a ground under section 100 of the Act it must fail at the threshold. Allegations of corrupt practice are in the nature of criminal charges, it is necessary that there should be no vagueness in the allegations so that the returned candidate may know the case he has to meet. If the allegations are vague and general and the particulars of corrupt practice are not stated in the pleadings, the trial of the election petition cannot proceed for want of cause of action. The emphasis of law is to avoid a fishing and roving inquiry. It is therefore necessary for the Court to scrutinise the pleadings relating to corrupt practice in a strict manner.”

22. In *Jeet Mohinder Singh's* case (supra) Hon'ble Supreme Court observed that the appellant in the said case filed replication to the written statement filed by the respondent. It is in the replication that the appellant has come out with an averment that some amongst the electors, who were threatened by Shri Sangram Singh, SHO were Jagseer Singh (not examined), Dharminder Singh, PW 13, Jawsant Singh (not examined), Jagraj Singh (not examined), and Mander Singh (not examined). Here itself, we may observe that material facts and particulars as to commission of corrupt practice are required to be given in the election petition and not in the replication filed much after the expiry of period of limitation for filing election petition. The material facts and particulars alleged for the first time in the replication and not forming part of averments made in the election petition cannot be tried and cannot be made subject matter of issues framed by the Court. The learned Designated Election Judge has taken care to frame the issues only by reference to the averments made in the election petition and not by referring to the averments made for the first time in the replication. Firstly, the respondent does not have an opportunity of denying the averments whether facts or particulars, introduced for the first time in replication. Secondly as already stated, material facts and particulars as to corrupt practice are required to be supported by an affidavit in the prescribed proforma. The replication is not supported by any affidavit in the prescribed proforma.

23. Consequently, the objection application filed on behalf of the first respondent is allowed and the replication application dated 23-01-2019 insofar as it relates to paras 4 to 86 and the application under Order VII Rule 14 of CPC moved by the petitioners are rejected.

24. List this matter on 12-03-2019 at 2.00 PM for framing of issues. The parties may submit their proposed issues on the next date fixed in the matter.”

5. Thereafter, the matter was taken up on 27-03-2019 and on the said date following issues were framed by the Court :

“1. Whether once a person availed the benefit of reservation of Other Backward Caste, then he may be permitted to avail the benefit of reservation of Scheduled Castes ?

2. Whether the Returning Officer has erred in law while considering the candidature of Mr. Satyapal Singh Baghel alias Satyapal Singh Sikarwar for a seat reserved for the persons of Scheduled Castes ?

3. Whether a person, who is not a member of Scheduled Castes, can avail the benefit of Article 334 of Constitution of India?

4. Whether the candidature of Mr. Satyapal Singh Baghel *alias* Satyapal Singh Sikarwar is ab-initio not maintainable as the returned candidate Mr. Satyapal Singh Baghel *alias* Satyapal Singh Sikarwar is not an eligible candidate to contest the election for a reserved seat because he belongs to Gadaria Caste (OBC) or Thakur (General) Caste by his own declaration and documents. Gadaria caste is notified as a member of Other Backward Classes in the Schedule published under the provisions of Uttar Pradesh (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 ?

5. Whether paragraph nos. 5 to 7 and 7A to 7L of the election petition are vague and do not contain any material facts and the same are liable to be struck off from the pleading under Order VI Rule 16 of the Code of Civil Procedure, 1908 ?

6. Whether the election petition is liable to be dismissed under Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908 ?

7. Whether the averments made in the election petition lack material facts and particulars and do not disclose any cause of action? If so, its effect?

8. Whether the Caste certificate or verification order of the District Level Caste Scrutiny Committee can be verified in the election petition, as Competent Legal Forum is available to the petitioner under the law as per judgement passed by Apex Court and this Court?. If not, its effect ?

9. Whether the election petitioner has no locus standi to maintain the present election petition under section 81 (1) of the Representation of the People Act, 1951, as he is not an "elector" from the constituency in question, as such the election petition deserved to be summarily dismissed on this ground alone ?

10. Whether the election petition has not been presented within the limitation period of 45 days as provided under Section 81 (1) of the Representation of the Peoples Act, 1951 and the same is fatal to maintainability of the election petition, as such the election petition is deserved to be summarily dismissed on this ground alone ?

11. Whether the copy of the election petition supplied to the respondent no.1 has been attested to be true copy of election petition under his own signature of the petitioner, as required under the provisions of Section 81 (3) of the Representation of the People Act, 1951 ? It not, its effect ?

12. Whether the election petitioner has not filed the valid affidavit in support of his pleading in the election petition nor verified the pleadings of the election petitions as required under the provisions of the Representation of the People Act, 1951/Civil Procedure Code, 1908. Therefore the election petition is not maintainable and liable to be dismissed by this Court ?

Parties are permitted to file documentary evidence within 10 days. Thereafter, within a week, they may complete exercise of admission and denial of document(s) and shall also submit list of witness(es), if any.

Put up this matter on 17.4.2019 at 2 PM in additional cause list”

6. Meanwhile, the general elections for Lok Sabha were held in the year 2019 and the respondent no.1 was elected to Lok Sabha from Agra Constituency as a member of Bhartiya Janta Party. Consequently, the respondent no.1 had submitted his resignation before the Competent Authority *i.e.* Speaker of Legislative Assembly, U. P. on 4<sup>th</sup> June, 2019 from the Member of Legislative Assembly, U. P. Constituency No. 95 (Tundla Constituency). The Competent Authority has accepted the resignation of the respondent no.1 on the same date and issued a notification dated 4.6.2019. Consequently, the vacancy of Member of Legislative Assembly for Tundla Constituency has arisen and the Secretariat of Legislative Assembly, Uttar Pradesh has notified the said vacancy to the Election Commission of India for conducting the bye-election for filling up the said seat. The respondent no.1 has filed the aforesaid applications for dismissing the Election Petition Nos.12 of 2017 and 13 of 2017 filed by Rakesh Babu, as infructuous.

7. In this backdrop, Shri Sushil Kumar Srivastava, learned counsel for the respondent no.1 submitted that the general election for U. P. Legislative Assembly was notified on 17.1.2017 and held by the Election Commission of India in various stages. In the said constitution the polling took place on 11.2.2017 and the result was declared on 11.3.2017 in which the respondent no.1 was declared as elected. The petitioners filed the election petitions challenging the election of respondent no.1 on the ground of qualification (caste certificate). The respondent no.1 filed his preliminary objections dated 15.4.2018 regarding maintainability of the election petitions stating that the petitioners have filed the election petitions in contravention of the mandatory provisions of Sections 81, 82, 83 of Representation of the People Act, 1951 and the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908. Therefore, the election petitions are liable to be dismissed under Section 86 (1) of the Act of 1951 and under Chapter VII Rule 11 of CPC. The respondent no.1 filed Civil Misc. Application dated 25.2.2019 under Order VII Rule 11 of CPC raising the preliminary objections that the election petitions are contrary to the mandatory provisions of the Representation of the People Act, 1951 and Code of Civil Procedure. The respondent no.1 filed the written statement categorically denying the averments and allegations made in the election petition. The respondent no.1 is a member of Dhangar caste by birth. Since Dhangar is notified as Scheduled Caste at Entry No.27 for State of Uttar Pradesh in the Presidential Order, 1950 (The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950 issued by Hon'ble President of India in exercise of power conferred by clause (1) of Article 341 of the Constitution of India, therefore he belongs to the Scheduled Caste category. As per judgment of Hon'ble Apex Court in *Madhuri Patil vs. Additional Commissioner Tribal Development*, 1994 (6) SCC 241, his caste certificate has been scrutinized and verified by the District Level Caste Scrutiny Committee on 21.4.2017. The petitioners have alternative remedy to approach the Division Level Appellate Scrutiny Committee and State Level Appellate Forum assailing the validity of the caste certificate of the respondent no.1.

8. Shri Sushil Kumar Srivastava has further submitted that the respondent no.1 has submitted his resignation on 4.6.2019 from the Tundla Constituency. The competent authority has accepted his resignation on the same date and issued the notification dated 4.6.2019 to give effect to the said resignation since 4.6.2019. Thus the vacancy of Member of Legislative Assembly for Tundla Constituency has arisen and the Secretariat of Legislative Assembly, U. P. has notified the said vacancy to the Election Commission of India for conducting the bye-election for filling up the said post. Therefore, the relief no.1, as claimed by the petitioner, has become infructuous. So far as the provision for claiming the relief with regard to declaration, that the election petitioner Rakesh Babu has been duly elected, is concerned, the same is provided in Section 84 of Representation of the People Act, 1951. The provision of ground, for which the petitioner may be declared to have been elected, is provided in Section 101 of the Representation of the People Act, 1951. In view of the aforesaid provision of Section 101 of the Act of 1951, the election petitioner cannot be declared as elected as neither he has properly proved in the election petition that he has

received a majority of valid votes nor he has challenged the election of the respondent no.1 on the ground of corrupt practices. As such, the relief claimed by the petitioner in the election petition cannot be granted and the election petitions have been become infructuous.

9. It is also sought to be contended that so far as grounds for challenging the election is concerned, the provision of ground for challenging the election is provided in Section 100 of the Act of 1951 and the provisions of corrupt practices are provided in Section 123 of Part VII, Chapter-I of the Act of 1951. After acceptance of the resignation of the respondent no.1 from the Tundla Constituency, the cause of action of filing the election petitions has been become infructuous. The said vacancy has arisen and the same has also been notified to the Election Commission of India for filling up the said vacancy through bye-election. The provision with regard to bye-election is provided under Part IX Section 147 to 151A of the Act of 1951. Section 150 provides for casual vacancy in the State of Legislative Assemblies. Section 151A provides that said bye-election for filling up the said vacancy shall be held within a period of six months from the date of occurrence of the vacancy. Therefore, the election petitions are liable to be dismissed as infructuous. He further submitted that if the trial in the election petition is allowed to proceed further, it would only be academic and a futile exercise. Any favourable verdict in the election petition will have far-reaching similar legal consequences to the respondent no.1 on his election to the Member of Parliament. If the pleas of the election petitioner herein concerning the caste certificate of the respondent no.1 were to be upheld, the same would have an adverse impact on the respondent no.1 in respect of his election to the Member of Parliament.

10. While raising objection and making prayer for dismissal of election petitions as infructuous being on the ground of academic residue, learned counsel for the respondents has relied upon the judgments of Hon'ble Supreme Court in Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu reported in AIR 1974 SC 505; Prakash Khandre vs. Dr. Vijay Kumar Khandre and others reported in (2002) 5 SCC 568; Dhartiakar Madan Lal Agarwal vs. Rajiv Gandhi; (2000) 10 SCC 145; the judgment of this Court in Chandra Mohan Shukla vs. Anil Dhirubhai Ambani and 11 others reported in 2010 (10) ADJ 63 (LB) as well as the judgement of High court of Andhra Pradesh in Ramesh Chennamaneni & another vs. Aadi Sreenivas & others reported in 2011 (6) ALD4.

11. On the other hand, Shri Rakesh Kumar Gupta, Advocate appearing for the election petitioners submitted that the first respondent is not eligible to hold any constitutional post. The privilege and rights available to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates can be conferred upon a particular class or caste only by the Parliament. Under Article 341 (1) of the Constitution of India the List of Scheduled Caste with respect to any State can be notified only by a Presidential order after consultation with Hon'ble Governor of that State by public notification. The Presidential Order, 1950 was amended by Amendment Acts in 1956 and 1976 and thereafter in the year 1991 in which in Part 18 of the Schedule only 66 castes were notified as Scheduled Caste for the State of U. P. The Presidential Order or the notification of the State Government does not include any sub-caste for any of the 66 notified Scheduled Castes. The State Government does not have a power to expand the notified Scheduled Caste by adding any sub-caste, race, tribe or any group within that caste. The Courts have not been given powers to expand the scope of the caste by adding sub-caste. The controversy requires hearing on merit as relief no. 1 still survives and in case, election is declared null and void the respondent no.1 may suffer punitive action under Article 104 of the Constitution of India.

12. The Court has perused the record and considered the arguments advanced by the parties. The respondent no.1 has filed the aforesaid applications for dismissing the Election Petition Nos.12 of 2017 and 13 of 2017 as infructuous, because the respondent no.1 submitted his resignation and the same has been accepted by the competent authority. The general elections for Lok Sabha were held in the year 2019 and the respondent no.1 has been elected to Lok Sabha from Agra Constituency. Thus, the grounds taken in the election petitions have been rendered of academic importance and the academic questions should not

ordinarily be decided by the Courts. It was further submitted that this election petition had not been filed by the petitioners on the ground of corrupt practice. Therefore, it was urged that the election petition might be dismissed as infructuous. It is not alleged that the returned candidate herein to have indulged in any corrupt practice within the meaning of Section 123 of Representation of People Act and the alleged disqualification does not entail in any electoral disqualification under Section 8-A thereof. Even if the question in controversy about the legality and validity of the caste certificate obtained by him with reference to the subject election was to be adjudicated herein adverse to his interest, the question may not be a living issue between the parties in the present election petitions and after acceptance of his resignation, any declaration that his election was illegal or void, could have no impact on the returned candidate and any exercise of continuance of proceedings in the election petitions would be a futile exercise to bring back a dead issue to life.

13. In *Loknath Padhan v. Birendra Kumar Sahu* (supra) Hon'ble Apex Court dealt with the well settled practice recognized and followed in India that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties, and pointed out that if an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it. Following *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Jervis* 1944 AC 111, the Apex Court held that an academic question, the answer to which cannot affect the position of one party or the other or which has no bearing on some right or liability in controversy between the parties, will be unnecessary and inexpedient to be decided and the Court would properly decline to decide. With reference to the election dispute before it in that case, involving alleged disqualification of the returned candidate due to subsistence of five Government contracts with the Government of Orissa, the Apex Court held that even if it is found that the candidate was so disqualified, it would have no factual consequence, as invalidation of election after dissolution of the House would be meaningless and ineffectual and as it would have no consequences operating in future, as it is the only facts existing on the date of nomination that would have relevance. The Apex Court distinguished the cases in which allegations of corrupt practices are involved in view of Section 8-A of RP Act under which a person found guilty of corrupt practices by an order under Section 99 will incur electoral disqualification up to six years from the date of the order in that regard. The trial of an election petition must proceed to its logical end in such case, as held in *Sheodhan Singh v. Mohan Lal* (1969) 1 SCC 408, but the principle was held by the Apex Court to be not applicable to disqualification, which has no other consequence than that of making the particular election void and which does not entail any electoral disqualification for the future. In that case, in view of the dissolution of the Legislative Assembly, the Apex Court considered the question of disqualification to be purely academic and dismissed the appeal against the decision in the election petition as futile.

14. In *Sohan Lal v. Asha Ram and others* (1981) 1 SCC 106, a three-Judge Bench of the Apex Court disposed of an election appeal without adjudication due to dissolution of the Assembly, fresh elections having taken place and a fresh House coming into existence notwithstanding any substantial grievance for the election petitioner, as the subsequent events rendered the litigation wholly unreal making it waste of the Court's time to consider the issues.

15. In *Podipireddy Atchuta Desai vs. Chinnam Joga Rao and others* (1987 (Supp) SCC 42), the Apex Court has held as under-

“The question raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be undertaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any views, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs.”

16. In *Kashi Nath Mishra v. Vikramaditya Pandey and others* (1998) 8 Supreme Court Cases 735, another three-Judge Bench of the Supreme Court dismissed an election appeal as infructuous, where the term of Assembly expired by efflux of time and another election was held and another Assembly was constituted. Similar was the decision of another three-Judge Bench of the Apex Court in *Romesh v. Ramesh K. Rana and others* (2000) 9 Supreme Court Cases 265, wherein the request was for recount of votes without any allegations of commission of any corrupt practice and in the meanwhile the Assembly itself was dissolved. The Apex Court considered that nothing further survives for consideration and dismissed the election appeal.

17. In *Kashi Nath Mishra vs. Vikramaditya Pandey and others* ((1998) 8 SCC 735), an appeal was filed before the Apex Court from the Election Petition No.4 of 1991 filed under Section 81 of Representation of the People Act, 1951. The appellant had challenged the election of the second respondent to the U.P. Legislative Assembly from the 227 Ballia Assembly Constituency in District Ballia. That petition was dismissed. The term of the assembly has expired by efflux of time and thereafter, another election has been held and another Assembly constituted. Under these circumstances, the appeal having become infructuous was dismissed without costs.

18. In the case of *Rajiv Gandhi (supra)* wherein the allegation with regard to corrupt practice was raised, Hon'ble Supreme Court observed that since allegation was with regard to corrupt practice and the matter is stale and academic but it may be heard. relevant portion of the judgment is reproduced hereinafter-

"In fact, during the course of hearing the appellant himself stated before us more than once, that it would now every difficult for him to produce evidence to substantiate the allegations of corrupt practice but none the less he insisted for the appeal being heard on merit. Though the matter is stale and academic yet having regard to the present state of law, we had to hear the appeal at length."

19. However, their Lordship had dismissed the appeal holding that the appellant cannot be permitted to waste the court time with permission to amend the appeal. The conclusive observation made by Hon'ble Supreme Court is as under-

"When this appeal came up for hearing before us the appellant insisted that he should be allowed to argue the case by putting on a crown (an artificial one) on his head. According to him without the crown he would not be able to make his submissions in a satisfactory manner. We refused to grant the permission to the great dissatisfaction of the appellant. A court of law is a solemn place where proceedings are held in a solemn manner and the time of the court especially in the Apex Court is precious time which belongs to the people and it would be wholly obnoxious to judicial propriety to allow a litigant to appear in court wearing a crown to argue the case. The Court cannot be converted into a dramatic or theatrical stage. We accordingly refused to grant the permission to the appellant to wear his crown."

20. In *Mundrika Singh Yadav vs. Shiv Bachan Yadav and others* {(2005) 12 SCC 211}, an election petition under sections 80 and 80-A of the Representation of the People Act, 1951 filed by the appellant was dismissed by the High Court. In the above said election petition, the appellant had sought for the relief of recount of ballot papers. The High Court on trial found a case in that regard having not been made out. The election to the Bihar State Assembly forming subject-matter of the election petition was held in the year, 2000. The term of the Legislative Assembly was over. Fresh elections were being held. Under these circumstances, the Apex Court has held that no relief could be allowed to the appellant in this appeal even if this appeal is allowed. The appeal was rendered infructuous and was dismissed accordingly.

21. Hon'ble High Court of Andhra Pradesh had also come across with similar controversy in *Ramesh Chennamaneni & another vs. Aadi Sreenivas & others* 2010 0 Supreme (AP) 635 and opined that



for according the relief under section 98 (c) of RP Act there are three alternatives available to the High Court in making an order at the end of trial of an election petition and the relief that may be claimed under section 84 which may be granted under section 101 is permissible, only if the election petitioner or such other candidate received a majority of valid votes or would have received a majority of valid votes, but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practice. In the present matter, as per pleading the applicant herein neither received a majority of valid votes nor did he claim the returned candidate to have obtained the votes secured by him by corrupt practices within the meaning of Section 123 of RP Act. Corrupt practices and electoral offences under RP Act were enumerated in Part-VII thereof and the self-contained provisions cannot be expanded or extended by implication or inference to cover any situations not specified as corrupt practices or electoral offences by RP Act. Relevant paragraphs of the said judgement are extracted as follows-

“22. Though the Division Bench would not definitely hold such a declaration in favour of the election petitioner to be not possible in the absence of availability of true facts, it was specifically observed that even if only two candidates contested, the Court in its discretion may always deny such relief under sections 84, 98(c) and 101 of RP Act and consequently, it directed conduct of By-election for this Constituency also irrespective of any possible adverse decision against the elected candidate, who since resigned, in the election petition. The election petitioner himself in his counter affidavit to this petition admitted that there is no provision in RP Act dealing with a situation where an election is being held in a Constituency, while an election petition concerning the previous election to that Constituency is pending. The general principle that all subsequent actions in respect of the subject matter of Court proceedings will be subject to such Court proceedings attempted to be canvassed as applicable to such situations, is not shown by the authority of any precedent to be so applicable. The relief under section 98(c) of RP Act is one of the three alternatives available to the High Court in making an order at the end of trial of an election petition and the relief that may be claimed under section 84 which may be granted under Section 101 is permissible, only if the election petitioner or such other candidate received a majority of valid votes or would have received a majority of valid votes, but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practice. The election petitioner herein neither received a majority of valid votes nor did he claim the returned candidate to have obtained the votes secured by him by corrupt practices within the meaning of Section 123 of RP Act. Corrupt practices and electoral offences under RP Act were enumerated in Part-VII thereof and the self-contained provisions cannot be expanded or extended by implication or inference to cover any situations not specified as corrupt practices or electoral offences by RP Act. The challenge to the election of the 1st respondent is on the ground of his being not qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of a State with reference to Section 5 of RP Act and Article 173 read with Article 191(1)(d) of the Constitution of India. The allegation of making false statements and suppressing the facts amounting to fraud in connection with acquisition of certificate of registration under the Citizenship Act, 1955 from the Government of India by the 1st respondent, is not covered by any corrupt practices under section 123 or an electoral offence under sections 125 to 136 of RP Act. While Section 101(b) does not refer even to the electoral offences under RP Act, as the right to be elected and the right to challenge an election are purely statutory creations, the provisions of such Statutes liable to be strictly and literally construed may not be susceptible to any elasticity in construing situations akin or similar to the defined corrupt practices to be also within the scope and ambit of Section 101 of RP Act enabling any declaration of the election petitioner as duly elected, even if the procurement of the citizenship certificate is found to be vitiated by any factor including fraud.

23. If so, either due to the principle laid down in *Vishwanatha Reddy v. Konappa Rudrappa Nadgouda* (1 supra) or due to the binding conclusions of the Division Bench in W.P. No. 14443 of 2010, dated 30-06-2010 or due to the statutory backdrop vis--vis the alleged ground of challenge to the election of the returned candidate, any legal possibility of the election petitioner being declared as duly elected in the earlier election appears too distinct and remote, if not impossible.

24. If it were so, the remaining relief capable of consideration in the event of the election petition being taken to its logical conclusion, is the declaration of the election of the 1st respondent as member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 28-Vemulawada Assembly Constituency in the General Elections to the said Assembly in 2009, to be illegal and void on the ground of his being not qualified to be an elector in that Constituency or to contest the election at the relevant time. However, much before any such eventuality could materialize, the returned candidate resigned, the seat was declared to have fallen vacant and the Election Commission of India is conducting By-election in that Constituency for the remaining term of the Legislative Assembly. The election petition is, hence, claimed to have become infructuous by the 1st respondent and to be not so by the election petitioner.

25. The Apex Court dealt with the well settled practice recognized and followed in India that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties, in *Loknath Padhan v. Birendra Kumar Sahu* (1974) 1 Supreme Court Cases 526 and pointed out that if an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it. Following *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Jervis* 1944 AC 111, the Apex Court held that an academic question, the answer to which cannot affect the position of one party or the other or which has no bearing on some right or liability in controversy between the parties, will be unnecessary and inexpedient to be decided and the Court would properly decline to decide. With reference to the election dispute before it in that case, involving alleged disqualification of the returned candidate due to subsistence of five Government contracts with the Government of Orissa, the Apex Court held that even if it is found that the candidate was so disqualified, it would have no factual consequence, as invalidation of election after dissolution of the House would be meaningless and ineffectual and as it would have no consequences operating in future, as it is the only facts existing on the date of nomination that would have relevance. The Apex Court distinguished the cases in which allegations of corrupt practices are involved in view of Section 8-A of RP Act under which a person found guilty of corrupt practices by an order under section 99 will incur electoral disqualification up to six years from the date of the order in that regard. The trial of an election petition must proceed to its logical end in such case, as held in *Sheodhan Singh v. Mohan Lal* (1969) 1 SCC 408, but the principle was held by the Apex Court to be not applicable to disqualification, which has no other consequence than that of making the particular election void and which does not entail any electoral disqualification for the future. In that case, in view of the dissolution of the Legislative Assembly, the Apex Court considered the question of disqualification to be purely academic and dismissed the appeal against the decision in the election petition as futile.

26. The returned candidate herein also was not alleged to have indulged in any corrupt practice within the meaning of section 123 of RP Act and the alleged disqualification does not entail in any electoral disqualification under section 8-A thereof. Even if the question in controversy about the legality and validity of the citizenship certificate obtained by him with reference to the subject election were to be adjudicated herein adverse to his interest, he will not be permanently debarred from acquiring Indian Citizenship in future in accordance with law and as the possibility of any adverse consequences to the 1st respondent in case of his failure in the election petition, is not regarding the right or liability in controversy between the parties in this election petition, the question may not be a living issue between the parties in the present election petition and after acceptance of his resignation, any declaration that his election was illegal or void could have no impact on the returned candidate and any exercise of continuance of proceedings in the election petition would be a futile exercise to bring back a dead issue to life.

28. However, the principles laid down by the Supreme Court in *Satrucharla Vijaya Rama Raju v. Nimmaka Jaya Raju and others* (2006) 1 Supreme Court Cases 212 run counter to any such possibility and the Apex Court followed the earlier decision in *C.M. Arumugam v. S. Rajgopal* (1976) 1 Supreme Court Cases 863, wherein it was held that every election furnishes a fresh cause of action for a challenge to that

election and an adjudication in the prior election petition cannot be conclusive in the subsequent proceeding and even if the cause of action in the earlier election petition merged in the final adjudication therein, the merger of the earlier cause of action with the decision therein cannot bar the trial of the fresh cause of action arising out of the subsequent election. Even regarding the status of a person or jural relationship of a person, the Apex Court held that an election petition under section 80 of RP Act cannot be held to lead to an adjudication which declares, defines or otherwise determines the status of a person or a jural relation of that person to the world generally and it is merely an adjudication of a statutory challenge on the question whether the election of the successful candidate is liable to be voided on any of the grounds available under section 100 of RP Act. The election petition was held to be not an action for establishing the status of a person or an action initiated by a person to have his status established or his jural relationship to the world generally established. A judgment in an election petition was also held to be not a judgment in rem specifically recognized by Section 41 of the Evidence Act and it was noted that the challenge to an election is only a statutory right and an election petition is not a suit of general nature or a representative action for adjudication of the status of a person. The best status that can be assigned to the judgment in an earlier election petition was held by the Apex Court to be that it is of a high evidentiary value while considering the case of the parties in the present election petition. The Apex Court also declined to treat the decision in the earlier election petition as a judicial precedent and on the facts of that case, it had, in fact, concluded that the conclusion in the previous case was based on an appreciation of the evidence adduced in that case, which would not operate as *res judicata* and which by itself is not sufficient to rebut the evidence available in the subsequent case, based on which a finding has been rendered. Therefore, any adjudication in the present election petition either about the citizenship status of the 1st respondent or the legality and validity of the citizenship certificate obtained by him or his registration as elector, the same will be only a piece of evidence in any subsequent proceeding, which has to be decided on its own merits on the effect of the totality of the evidence in that case.

38. Though no provision of the RP Act provides for a specific order of dismissal on the ground of infructuousness including in respect of the appeals before the Supreme Court under sections 116-A to 116-C of RP Act, the Apex Court dismissed the election appeals on that ground and section 98 of RP Act in clause (a) provides for an order of dismissal of an election petition, of course, at the conclusion of the trial and the procedures for trial prescribed by Sections 86, 87 and other provisions of RP Act make the procedure applicable under the Code of Civil Procedure, 1908 to the trial of suits applicable as nearly as may be to the election petitions. The proviso to Section 87 (1) of RP Act confers discretion on the High Court to refuse for reasons to be recorded in writing to examine any witness or witnesses, if it is of the opinion that the evidence of such witness or witnesses is not material for the decision of the petition. Recourse can be had to the said proviso to refuse to examine any witnesses in the election petition and conclude the trial to make an order under section 98 (a) of RP Act. In that view, the High Court is not barred from taking recourse to such action, which, in fact, is the procedure adopted by the Apex Court itself in appropriate cases as illustrated by the four precedents cited above.

39. Thus, on a comprehensive consideration of the facts and circumstances of the case, the admitted developments subsequent to filing of the election petition including the resignation by the 1<sup>st</sup> respondent, its acceptance by the Speaker, the notification of the vacancy by the Legislature Secretariat and the By-election in progress in pursuance of the directions of this Court in W.P. No.14443 of 2010, apart from the pendency of W.P. No. 3737 of 2010 on the question of the statutory action under section 10 of the Citizenship Act, 1955 concerning the 1<sup>st</sup> respondent, make the continuance of the election petition improper and unreasonable and the election petition can be considered to have become superfluous and infructuous. It has

to be accordingly, dismissed without expressing any opinion on the questions in controversy in the election petition about the citizenship certificate or citizenship status or registration as elector, of the 1<sup>st</sup> respondent.”

22. In *Prakash Khandre vs. Dr. Vijaya Kumar Khandre and ors* reported in 2002 (4) Supreme 294 Hon'ble Supreme Court dealt with the same question and observed in following paragraphs as under-

“14. However, in an election where elected candidate is declared to be disqualified to contest election and there are more than two candidates contesting election, there is no specific provision under the Act under which the person who has secured the next highest number of votes could be declared as elected. The Act is silent on this point. Further, it cannot be presumed that the votes secured by the disqualified elected candidates would have been wasted or would have been secured by the next candidate who has secured more votes. If disqualified candidate was not permitted to contest the election then how the voters would have voted in favour of the candidate who has secured more votes than other remaining candidates would be a question in the realm of speculation and unpredictability. In such a situation, declaring the election of the returned candidate on the ground of his initial disqualification to contest the election by itself would not entitle the election petitioner or any other candidate to be declared elected.

15. The learned counsel for the parties referred to various decisions rendered by this Court and we would refer them in Chronological Order. The Constitution Bench of this Court in *Konappa Rudrappa Nadgouda v. Vishwanath Reddy* and another [(1969) 2 SCR 90] dealt with the case where one Vishwanath Reddy was declared elected to Mysore Legislative Assembly and that election was challenged by Nadgouda who was a contesting candidate on the ground that Reddy was disqualified from standing as a candidate for election. This Court by order dated 19th July, 1968 held that election of Reddy was void and that votes cast in his favour be treated as thrown away. The Court held "as there was no other contesting candidate, we declare the appellant (election petitioner) as elected to the seat from the Yadgiri Constituency." That order was challenged by filing a review application which was granted and question whether it was open to the Court on finding recorded about disqualification of Reddy to declare Nadgouda as duly elected to the Mysore Legislative Assembly was dealt with and decided. The Court referred to earlier decision in *Keshav Laxman Borkar v. Dr. Devrao Laxman Anande* [(1960) 1 SCR 902], wherein it was held that a candidate whose nomination paper is accepted after scrutiny, is a validly nominated candidate "at least for the purpose of receiving votes at the election", and that the candidate must be treated as a person for whom votes could be given. The Court on that view held that where there are only two candidates for a seat and the election of the candidate declared elected is set aside on the ground that he was disqualified, the defeated candidate cannot be declared elected, and there must be a fresh election. In the opinion of the Court the votes cast in favour of the disqualified candidate cannot be said to be thrown away unless there is a "special pleading" that certain voters had cast their votes with the knowledge or notice that the candidate for whom they had voted was not eligible for election, and they had deliberately thrown away their votes in favour of the disqualified person; in the absence of such a plea it cannot be said that the votes cast in favour of a person who was by law disqualified from being nominated, but who was in fact nominated, were thrown away. In the opinion of the Court a defeated candidate out of the two who contested the election may be declared elected under section 84 read with section 101 of the Act, if he proves that the voters had notice of the disqualification of the successful candidate.

16. The correctness of the said view was challenged before the Constitution Bench. The Court considered various English decisions cited at the bar and observed that the cases decided by the Courts in the United Kingdom appear to have proceeded upon some general rule of election law that the votes cast in favour of a person who is found disqualified for election may be regarded as thrown away only if the voters had notice before the poll of the disqualification of the candidate. Thereafter, the Court pertinently observed but in our judgment the rule which has prevailed in the British Courts for a long time has no application in our country. The rule enunciated in U.K. has only the merit of antiquity; the rule cannot be extended to the trial of disputes under our election law, for it is not consistent with our statute law, and in any case the conditions prevailing in our country do not justify the application of that rule. The Court also considered Section 53 of the Act and held that it renders a poll necessary only if there are more candidates contesting the election than the number of seats contested and if the number of candidates validly nominated is equal to the seats to be filled, no poll is necessary and where by an erroneous order of the Returning Officer poll is held which, but for that order, was not necessary, the Court would be justified in declaring those contesting candidates elected, who, but for the order, would have been declared elected.

17. Thereafter, the Court observed thus: (AIR p.608 para 12) :

"When there are only two contesting candidates, and one of them is under a statutory disqualification, votes cast in favour of the disqualified candidate may be regarded as thrown away, irrespective of whether the voters who voted for him were aware of the disqualification. This is not to say that where there are more than two candidates in the field for a single seat, and one alone is disqualified, on proof of disqualification all the votes cast in his favour will be discarded and the candidate securing the next highest number of votes will be declared elected. In such a case, question of notice to the voters may assume significance, for the voters may not, if aware of the disqualification have voted for the disqualified candidate."

18. The Court also considered Section 101 and held as under: (AIR pp.608-09 para 13):

"The votes obtained by corrupt practice by the returned candidate, proved to be guilty of corrupt practice, are expressly excluded in the computation of total votes for ascertaining whether a majority of votes had been obtained by the defeated candidate, and no fresh poll is necessary. The same rule should, in our judgment, apply when at an election there are only two candidates and the returned candidate is found to be under a statutory disqualification existing at the date of the filing of the nomination paper."

19. In *Thiru John and Another v. Returning Officer and Others* [1977 (3) SCR 538], the Court dealt with the biennial election to the Rajya Sabha from the State of Tamil Nadu where the voting pattern is single-transferable vote wherein the elected candidate Shri John was found by the Court to be statutorily disqualified for election. The Court considered the question whether the votes secured by such candidate be regarded as 'thrown away' and in consequence the next candidate be declared elected? In that context the Court observed: -

"55. Again, the answer to this question, in our opinion, must be in the negative. It is nobody's case that the electors who voted for Shri John, had at the time of election, knowledge or notice of the statutory disqualification of this candidate. On the contrary, they must have been under the impression that Shri John was a candidate whose nomination had been validly accepted by the Returning Officer. Had the electors notice of Shri John's disqualification, how many of them would have voted for him and how many for the other continuing candidates,

including Sarv Shri Subramanyan and Mohan Rangam, and in what preferential order, remains a question in the realm of speculation and unpredictability."

20. The Court also referred to the following observations made by Hidayatullah, C.J. speaking for the Court in *R.M. Seshadri v. G.Vasantha Pai* [1969 (1) SCC 27] rejecting similar contention-

"This (question) will depend on our reaching the conclusion that but for the fact that voters were brought through this corrupt practice to the polling booths, the result of the election had been materially affected. In a single transferable vote, it is very difficult to say how the voting would have gone, because if all the votes which Seshadri had got, had gone to one of the other candidates who got eliminated at the earlier counts, those candidates would have won. We cannot order a recount because those voters were not free from complicity. It would be speculating to decide how many of the voters were brought to the polling booths in car. We think that we are not in a position to declare Vasanta Pai as elected, because that would be merely a guess or surmise as to the nature of the voting which would have taken place if this corrupt practice had not been perpetrated."

And, thereafter the Court held as under-

"The position in the instant case is no better. It is extremely difficult, if not impossible, to predicate what the voting pattern would have been if the electors knew at the time of election, that Shri John was not qualified to contest the election. In any case, Shri Subramanyan was neither the sole continuing candidate, nor had he secured the requisite quota of votes. He cannot therefore, be declared elected:"

21. The Court also considered the dictum in the case of *Viswanath (supra)* and observed that the ratio decidendi of said case is applicable only where (a) there are two contesting candidates and one of them is disqualified; and (b) the election is on the basis of single non-transferable vote.

22. Again in *Lata Devi (Mali) v. Haru Rajwar* [(1989) 4 SCC 773], this Court dealt with the same question and observed as under-

".It is to be noted that in an election petition what is called in question is the election and what is claimed is that the election of all or any of the returned candidate is void, with or without a further declaration that the election petitioner himself or any other candidate had been duly elected. Declaring the election of the returned candidate void does not, by itself, entitle the election petitioner or any other candidate to be declared elected."

23. Learned counsel for the appellant lastly referred to the decision in *D.K. Sharma v. Ram Sharan Yadav and Others* "[1993] Supp 2 SCC 117". In that case, the High Court referred to the decision in *Konappa Rudrappa Nadgouda (supra)* and held that on the basis of the oral evidence, it was not possible to hold that the voters who cast their votes in favour of the elected candidate did so after having noticed about the disqualification and knowing that their votes would be wasted and therefore, the second prayer of the election petitioner to declare him as duly elected after throwing away the votes of elected candidate, was not allowed. This Court did not find any infirmity in the said reasoning and, therefore, dismissed the appeal.

24. In view of the aforesaid settled legal position, in our view, the impugned order passed by the High Court declaring the election petitioner as elected on the ground that the votes cast in favour of elected candidate (appellant) are thrown away was totally erroneous and cannot be justified. As held by the Constitution Bench in Konappa's case that some general rule of election law prevailing in the United Kingdom that the votes cast in favour of a person who is found disqualified for election may be regarded as 'thrown away' only if the voters had noticed before the poll the disqualification of the candidate, has no application in our country and has only merit of antiquity. We would observe that the question of sending such notice to all voters appears to us alien to the Act and the Rules. But that question is not required to be dealt with in this matter. As stated earlier, in the present case for one seat, there were five candidates and it would be impossible to predict or guess in whose favour the voters would have voted if they were aware that elected candidate was disqualified to contest election or if he was not permitted to contest the election by rejecting his nomination paper on the ground of disqualification to contest the election and what would have been voting pattern. Therefore, order passed by the High Court declaring the election petitioner Dr. Vijay Kumar Khandre as elected requires to be set aside.

23. In *P.H. Pandian vs. P. Veldurai and another* (2013) 14 SCC 685, an appeal under section 116-A of the Representation of the People Act, 1951 was filed questioning the judgment and order made in the election petition in ELP.No.1 of 1996 on 29.12.1999. In this case, the Apex Court has observed that though fresh elections have since been held to Tamil Nadu Legislative Assembly and to an extent this appeal has been rendered infructuous, the manner in which the election petition was dealt with by the High Court causes us concern and that necessitates our making reference to some salient facts. Ultimately, the Apex Court has observed that it is a settled practice of Supreme Court not to pronounce upon matters which are only of an academic interest. Once the charge of corrupt practice fails, rest of the appeal would be rendered infructuous because fresh elections have already taken place and the old Assembly is no longer in existence. Even if the appellant was to succeed on the issue that the returned candidate had a subsisting contract with the Panchayat Union and the State Government and was, therefore, disqualified to be chosen for the seat under section 9-A of the Representation of the People Act, 1951, it would only be of an academic interest.

24. Whenever in a petition, which includes election petition, the relief claimed with regard to main issue involved becomes redundant or infructuous then for other relief Courts may exercise its discretion and may not proceed further in case right of the plaintiff or dependent satisfied or no grievance remained pending against defendant or respondents because of the change of circumstances. The Court may use its discretion to drop the proceeding and may not proceed further in a matter even if, some relief of academic nature stand survive.

25. In the present case, admittedly the respondent no.1 submitted his resignation on 4.6.2019 from the Tundla Constituency and the same has been accepted by the Competent Authority on the same date. The notification was issued on 4.6.2019 to give effect to the said resignation since 4.6.2019 and thus the vacancy of Member of Legislative Assembly for Tundla Constituency has arisen. The Secretariat of Legislative Assembly, U.P has also notified the said vacancy to the Election Commission of India for conducting the Bye-election for filling up the said post and therefore, the relief no.1, as claimed by the petitioner,

has become infructuous. It is consistent view of Hon'ble Supreme Court that time of the Court is precious one and academic exercise is not warranted unless still some relief may be granted to petitioner or the appellant may be followed. No allegations are levelled in the election petitions on corrupt practice and therefore, this Court finds that there is no impediment or obstacle in dismissing this petition as the prayer itself has become infructuous.

26. In view of the aforesaid discussion and in the light of the aforesaid decisions of Apex Court, I am of the considered view that nothing further survives in this matter. The aforesaid applications preferred by the respondent no.1 for dismissing the Election Petition Nos.12 of 2017 and 13 of 2017 as infructuous, are allowed.

27. Consequently both the election petitions are hereby dismissed as having been rendered infructuous.

Order dated : 03.3.2020 RKP.

(Sd.) MAHESH CHANDRA TRIPATHI, J.

By order,  
ANUJ JAIPURIAR,  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।





# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, ४ जुलाई, 2020 ई० (आषाढ़ 13, 1942 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् जहांगीराबाद, बुलन्दशहर

19 अक्टूबर, 2019 ई०

सं० 876/न०पा०परि०ज०बाद/2019-20-नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत “टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016” के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि (प्रारूप) बनायी है।

यह उपविधि टोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियम के सम्बन्ध में है। इस उपविधि (प्रारूप) की स्वीकृति नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद के बोर्ड के संकल्प दिनांक अगस्त, 2018 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसके सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित से समाचार में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उपविधि का प्रारूप नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद के सफाई विभाग कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध है व नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद की वेबसाइट [www.nppjahangirabad.in](http://www.nppjahangirabad.in) पर देखी जा सकती है। इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत् है-

### नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2018

**1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**(1) इस उपविधि का नाम नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद की “नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018” कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

**2-लागू होना-**यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी टोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर की सीमा में है पर लागू होगी।

3-इस उपविधि में जब तक कि इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है-

1-“अभिकरण या अभिकर्ता” से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबन्धन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीकरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

2-“जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबल वेस्ट)” से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रो आर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

3-“जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)” से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

4-“शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य” बायो डिग्रेडिबल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान-रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

5-“घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट” से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाइटें, अवधि समाप्त औषधियाँ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियाँ, प्रयुक्त सुइयाँ तथा सिरिंज और संदूषित पेट्टियाँ आदि से है।

6-“बायो-मीथेनेशन से तात्पर्य” ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

7-“द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य” घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

8-“विकेन्द्रित प्रसंस्करण” से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

9-“ब्रांड ओनर से तात्पर्य” ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

10-“निपटान से तात्पर्य” भू-जल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अन्तिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

11-“नगर निकाय” से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर से है।

12-“वृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 50 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

13-“संग्रहण” से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

14-“स्रोत पर संग्रहण” से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे घर-घर संग्रहण” भी कहा जा सकता है।

15-“सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र” से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

16-“कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य” ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्गत है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

17-“निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट” से तात्पर्य निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलबा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

18-“अपशिष्ट छँटाई केन्द्र” से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी या ढाँचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छँटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

19-“अपशिष्ट उत्पादक” से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

20-“निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य” किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

21-“कूड़ा कचरा से तात्पर्य” किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े, कागज, कपड़ा, लकड़ी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

22-“संग्रहण” से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहाँ पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

24-“मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)” से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।

25-“नगरीय ठोस अपशिष्ट” के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हो।

26-“गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन” से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

27-“अध्यासी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

28-“स्वामी से तात्पर्य” ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। “प्रसंस्करण” से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु।

29-उपयुक्त बनाने के प्रायोजन के लिये प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

30-“पुनर्चक्रण” से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान नहीं हो सकती है।

31-“कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य” नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंस के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

32-“प्रयोक्ता शुल्क” से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

33-“पृथक्करण” से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंस सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक् करने से है।

34-“छंटाई करना” से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक् करना सम्मिलित है।

35-“भण्डारण” से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

36-“परिवहन” से तात्पर्य नगरीय टोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

37-“विहित प्राधिकारी” में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है--

**ई-अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य-**

**प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता-**

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक् शाखाओं अर्थात् बायोडिग्रेडेबल (गीला कूड़ा), नान-बायोडिग्रेडेबल (सूखा कूड़ा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय-समय पर नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्गत या अधिसूचना के अनुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपर्स और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची-4 का भुगतान करेंगे जो टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये नगरपालिका परिषद् की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित कर अनुमति प्राप्त किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगरपालिका द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगरपालिका परिषद् द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगरपालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक पुनर्चक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगरपालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी बृहद अपशिष्ट सृजक नगरपालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगरपालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

### 3-प्रतिषेध-

(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्पातन पाइप और फिटिंगों में कोई कूड़ा कचरा या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो-

[1] जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुँचाने की,

[2] नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की, खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की,

(3) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही, पशुओं, वाहनों बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) [1] कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

[2] कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

[3] कोई भी पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गन्दगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

[4] कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी नहीं करेगा।

[5] कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

[6] कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।

[7] कोई भी व्यक्ति जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

[8] कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाई कर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उत्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

4-नगरीय टोस अपशिष्ट का संग्रहण-

(1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण-

[क] द्वार-द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कन्टेनरयुक्त हाथटेला/रिक्शा तथा एक घंटी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा निश्चित की गयी संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घंटी या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा निर्धारित समयावधि में एवं यथा निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा नहीं और उसे नगरपालिका परिषद् द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपेगा।

[ख] नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेंगे।

[ग] किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था सम्भव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण-होटल या रेस्टोरेन्ट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण-शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रति दिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय टोस अपशिष्ट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 में सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली, 2016 के अनुसार आदेशित हो।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध में लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि अपशिष्ट का भण्डारण करेंगे एवं नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक, नगर निकाय या उसका अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे जो उत्पादक से पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नान बायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगरपालिका परिषद् या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर किया जायेगा जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्रों को दिया जायेगा। वेस्ट पिकर्स-वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा। उन्हें अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर-घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी

संस्थाओं, लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को, संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत व अनुसूची दो में दी गयी है)।

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारम्भिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहाँ स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना सम्भव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट स्थल पर डाला जायेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथटेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले एवं नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

5-नगरीय टोस अपशिष्ट का पृथक्करण-

(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय टोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा-

[1] जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)

[2] जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)

[3] जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट

[4] घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

6-नगरीय टोस अपशिष्ट का भण्डारण-

(1) नगर निकाय नगरीय टोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थान पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहाँ किसी प्रकार का अपदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगर निकाय नगरीय टोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहाँ किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे खुले स्थान में हो या बन्द शेड में, जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान हो, से नगर निकाय नगरीय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय टोस का संग्रह किया जाता हो वहाँ टोस को पृथक-पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

7-सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र-

अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत टोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबन्धित अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहाँ से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर अधिसूचित करें।

8-ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था-

नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहाँ कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट काम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किये गये अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस, कुक्कुट हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति

9-सुविधा और सहायता  
उपलब्ध करना-

सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग प्लान्ट या जैव मीथेनीकरण प्लान्ट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

अधिशाली अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले विशेषज्ञों लाइसेंस प्राप्त कवाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नम्बर नगर निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेंगे। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

10-कूड़ा निस्तारण  
प्रभार एवं प्रयोक्ता  
शुल्क का लगाया  
जाना-

नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशाली अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लागू किया जायेगा जोकि अनुसूची-4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

11-कम्पोस्ट खाद को  
बनाया जाना-

अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनाये और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों में लगाये गये पेड़ों और आस-पास के पेड़ों में डालें। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

12-नगरीय ठोस अपशिष्ट  
का प्रसंस्करण-

(1) जहाँ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रदर्शन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों में इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात् उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छंट कर निकाला गया हो, को सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।



- (8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माइनिंग व बायो-रेमिडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।
- (9) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- (10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।
- 13-नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन- अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहाँ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिये (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढका रहेगा।
- 14-स्रोत पर ही एकत्रीकरण- भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुँचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।
- 15-सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र- अपवादिक मामलों में जहाँ स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहाँ नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहाँ आवश्यक और सम्भव हो, रख-रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।
- 16-अपशिष्ट छटाई केन्द्र- पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी उतने अपशिष्ट छटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और सम्भव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते हैं, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से खोखा मोड़ या गुमटी के रूप में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी। जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए “हरे रंग” के डिब्बे पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए “नीले रंग” एवं अन्य अपशिष्ट के लिए “लाल रंग” के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 17-समयसारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग- नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।
- 18-स्थानीय नागरिक समूह- स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तदोपरान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकें। सड़कों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया, माडल उपविधियां तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु

माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

#### 19-सफाई अभियान-

उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहाँ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

#### 20-जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण-

अधिकांश अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मों और उसके अधिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक यूनिटों, सकल एरिया सिटीजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में भौक्षिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

#### 21-अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन-

जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।

#### 22-शिकायतों का निस्तारण-

नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाइन कम्प्लेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकड़े ऑनलाइन ग्रिवान्स मैनेजमेन्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/सिटीजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

#### 23-नागरिकों की सफाई टीम-

अधिकांश अधिकारी, नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यों में विशेष रुचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्राही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

#### 24-रूचि की अभिव्यक्ति-

किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो-मिथेनीकरण आदि की अधिकांश अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

#### 25-आकस्मिक निरीक्षण

अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्यूनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने वार्डों के विभिन्न मार्गों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जांच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

#### 26-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में दायित्व-

##### (1) मलिन बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में दायित्व-

क-अधिकांश अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहाँ-जहाँ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डों के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने को अन्तर्गत) का विस्तार करेंगे।

ख-जहाँ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

ग-अपवादिक मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की

व्यवस्था की जायेगी जहाँ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहाँ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व-चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुँचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निषिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) **ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व-**घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुँचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(4) **नाली की सफाई का दायित्व-**घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुँचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहाँ ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) **पालतू पशु स्वामी का दायित्व-**किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतू पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) **सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व-**सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना-प्रदर्शन इत्यादि शामिल हैं) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करे।

नगरनिकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7) **निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य-**

(1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कोंच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(2) गैर नान बायोडिग्रेडबल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

(3) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरो के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

- (4) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।
- 27-नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति- उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1916 की में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।
- 28-अपराधों का प्रशमन- इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क की धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोष में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएं अपने पास रखेंगी और जहाँ अपराध का इस प्रकार प्रशमन-
- (क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतन्त्र कर दिया जायेगा।
- (ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहाँ प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।
- उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतन्त्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

#### अनुसूची-1

#### नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि-2018

#### प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी-			
	1-अपशिष्ट फैलाना/फेकना	200.00	प्रशमन शुल्क का पांच गुना	500.00
	2-थूकना	100.00	"	200.00
	3-मूत्र विर्सजन करना	100.00	"	250.00
	4-जानवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना	500.00	"	1,500.00
	5-वाहनों की धुलाई	500.00	"	1,500.00
	6-कपड़े धोना	500.00	"	1,500.00
	7-सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुण्ड में गन्दगी फैलाना	500.00	"	1,500.00
2	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर	500.00	"	5,000.00

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पट्टों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी करने/कराने पर	500.00	प्रशमन शुल्क का पांच गुना	5,000.00
4	पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गन्दगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर	500.00	"	1,000.00
5	नाले, नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर-			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000.00	"	5,000.00
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000.00	"	10,000.00
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000.00	"	20,000.00
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना	500.00	"	शून्य
7	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई	500.00	"	शून्य
8	किसी परिसर में 24 घण्टे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना	500.00	"	2,000.00
9	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण	1,000.00	"	-
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना-			-
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500.00	"	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	400.00	"	शून्य
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड /होटल	5,000.00	"	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	"	शून्य
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर	25,000.00	"	शून्य
12	थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर	25,000.00	"	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना-		"	
	(क) व्यक्तिगत भवन	200.00	"	
	(ख) दुकान/बूथ	500.00	"	
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/ होटल	5,000.00	"	
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	"	
	(ङ) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	5,000.00	"	
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000.00	"	
14	वृहद अपशिष्ट (50 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना	5,000.00 प्रतिमाह	10,000.00 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्ड्स वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर	2,000.00	4,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर	5,000.00	10,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	----
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	----
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पाँच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00	500.00	----
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छँटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	1,000.00
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर	1,000.00	2,000.00	----
23	खुले में शौच करने पर	500.00	100.00	----
24	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेंकना	500.00	1,000.00	5,000.00
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00	1,000.00	1,000.00
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के टेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए	100.00	200.00	----
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए	500.00	1,000.00	5,000.00
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनधिकृत रूप से पानी बहाने पर	1,000.00	2,000.00	----
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात् 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए	5,000.00	1,000.00	सफाई करने पर आने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपॉजिट जब्त कर लेना।

**नोट-1-**उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्ज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेंगी।

2-अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3-यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

## अनुसूची-2

## जैवनाशित और पुनर्चक्रिय अपशिष्ट की सूची

## जैवनाशित अपशिष्ट

(उदाहरणार्थ स्वरूप)

जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।

रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।

मांस और हड्डियाँ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।

पशुओं का कूड़ा करकट, गोबर सफाई के बाद घर की गंदगी, नारियल के छिलके, राख, अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

## पुनर्चक्रिय अपशिष्ट

(उदाहरणार्थ स्वरूप)

पुनर्चक्रिय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।

समाचार-पत्र, कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें शीशा, धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक फटे कपड़े चमड़ा रेक्सिन रबर, लकड़ी/फर्नीचर पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

## अनुसूची तीन

## जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

## जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनके सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

## 1-धारदार अपशिष्ट-

सुइयाँ, सिरिज, छुरियाँ, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों हैं।

## 2-बेकार दवाइयाँ और साइटोटाक्सिक औषधियाँ-

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाइयों के अपशिष्ट।

## 3-ठोस अपशिष्ट-

रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रुई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

## अनुसूची-4

## आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

क्र0 सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	यूजर चार्ज प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
1	भवन एक मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	30.00
2	भवन दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	40.00
3	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	50.00
4	भवन एक मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	60.00
5	भवन दो मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	80.00
6	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	100.00
7	भवन एक मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	70.00
8	भवन दो मंजिल (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	90.00
9	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक तक)	120.00
10	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	80.00
11	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	120.00
12	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	150.00
13	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	100.00
14	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	120.00
15	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	150.00

1	2	3
		रु0
16	व्यवसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (1001 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल तक)	120.00
17	व्यवसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (1001 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल तक)	150.00
18	व्यवसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल तक)	180.00
19	ऐसे भवन जिनमें दुकान/व्यवसाय हो रहा हो	उपरोक्तानुसार भवन एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के क्षेत्रफल के अनुसार
20	बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवार हेतु	10.00
21	कच्चे भवनों व अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार हेतु	5.00
22	पथ विक्रेता, पान/चाय/खोखा/टेले/सब्जी, फल आदि	50.00
23	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मीटर तक)	500.00
24	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मीटर से अधिक)	1,000.00
25	होटल, गेस्ट हाउस 30 कमरे तक	2,000.00
26	होटल, गेस्ट हाउस 30 कमरे से अधिक	2,500.00
27	होटल तीन सितारा एवं उससे अधिक	3,000.00
28	लाज 30 कमरे तक	2,000.00
29	लाज 30 कमरे से अधिक	3,000.00
30	धर्मशाला 30 कमरे तक	1,500.00
31	धर्मशाला 30 कमरे से अधिक	2,000.00
32	बैंक	1,500.00
33	सिनेमा हॉल	1,500.00
34	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मीटर तक)	2,000.00
35	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मीटर से अधिक)	5,000.00
36	स्कूल जिसमें 500 विद्यार्थी से कम हों	500.00
37	स्कूल जिसमें 500 या उससे अधिक विद्यार्थी हों	800.00
38	मॉल	5,000.00
39	क्लीनिक, डिस्पेन्सरी, मेडीकल स्टोर, डेंटल क्लीनिक, होम्योपैथी क्लीनिक, मेडीकल स्टोर, डिस्पेन्सरी, आयुर्वेदिक क्लीनिक, मेडीकल स्टोर डिस्पेन्सरी, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक, एम0आर0आई0 सेन्टर, सी0टी0 स्कैन सेन्टर	1,000.00
40	नर्सिंग होम/अस्पताल 30 शैया से कम	3,000.00
41	नर्सिंग होम/अस्पताल 30 शैया व उससे अधिक	5,000.00
42	छात्रावास 30 कमरे से कम	1,500.00
43	छात्रावास 30 कमरे या उससे अधिक	2,000.00
44	उच्च शिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	2,000.00
45	विश्वविद्यालय	5,000.00
46	कोचिंग इन्स्टीट्यूट 100 से कम विद्यार्थी	2,000.00



1	2	3
		रु0
47	कोचिंग इन्स्टीट्यूट 250 व उससे अधिक विद्यार्थी	3,000.00
48	वर्कशॉप/फैक्ट्री 1000 वर्ग मीटर से कम	1,000.00
49	वर्कशॉप/फैक्ट्री 1000 वर्ग मीटर से अधिक	2,000.00
50	पेट्रोल पम्प	2,000.00
51	शोरूम 1000 वर्ग फुट से कम	1,000.00
52	शोरूम 1000 वर्ग फुट से अधिक	1,500.00
53	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बीमा कार्यालय आदि	1,000.00
54	वाहन सर्विस सेन्ट (टू-व्हीलर)	1,000.00
55	वाहन सर्विस सेन्ट (फोर-व्हीलर)	2,000.00
56	लघु व कुटीर उद्योग (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट 10 कि०ग्रा0 प्रतिदिन	500.00
57	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट	3,000.00
58	उत्सव हाल एवं मेला, प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्गमीटर तक	2,000.00
59	उत्सव हाल एवं मेला, प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्गमीटर तक	5,000.00
60	अन्य जो ऊपर चिन्हित नहीं है।	नगरपालिका के आंकनल के अनुसार

**नोट-1-**प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2-यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3-विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

4-वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप में अवस्थ्य हों एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा। परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

5-जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत होगा।

6-प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पंचायत द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

डा० सूरजभान माहुर,  
अध्यक्ष,  
नगरपालिका परिषद्, जहांगीराबाद,  
जिला बुलन्दशहर।

## कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, देवरिया

27 फरवरी, 2020 ई0

सं0 2810/स0अनु0-2019-20/देवरिया-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, देवरिया अपने सीमान्तर्गत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2018 बनायी है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। उक्त नियमावली के सम्बन्ध में उसके बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, देवरिया को सम्बोधित करके लिखित रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनांक 30 दिन के अन्दर प्राप्त होगा। समय से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत न किये जाने की दशा में विचार किया जाना सम्भव न होगा। उक्त का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र, "राष्ट्रीय सहारा" में 14 दिसम्बर, 2018 को कराया गया था। आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

### उपविधि

#### 1-संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ-

- (1) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2018" कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद्, देवरिया में प्रभावी होगी।

#### 2-परिभाषाएँ-

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ;
- (2) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (3) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, देवरिया के अधिशासी अधिकारी से है।
- (4) "नगर पालिका" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, देवरिया से है।

#### 3-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/विविध-

- (1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।
- (2) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों मार्गों पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।
- (3) किसी स्वामी के मरे हुए बड़े जानवर उठाने पर रु0 2,000.00 प्रति पशु।
- (4) किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 1,000.00 प्रति पशु।
- (5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 3,000.00 प्रति प्रकरण।
- (6) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाउमिन/अण्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर डस्टबिन न होने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति दुकान।

- (7) गृह स्वामी के द्वारा अपने मकान के सामने कूड़ा डालने/बहाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति मकान, पुनरावृत्ति करने पर रु0 1,000.00 प्रति मकान, कूड़ा/कचड़ा जलाये जाने पर जुर्माना रु0 2,000.00 एवं पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति मकान।
- (8) सड़क के किनारे मोरंग, बालू, ईट भवन सामग्री (मलवा) पाये जाने, नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के बचे हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी ब्याह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके ऊपर उपरोक्त दर्शाये गये सामग्रियों/अतिक्रमण किये जाने पर उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपये) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- (9) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पालिका परिषद्, देवरिया द्वारा अनुबन्धित संस्था होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 200.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान तथा गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम, आदि बल्क गेस्ट हाउस, नाली पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 1,000.00 प्रति दिन एवं प्रति गेस्ट हाउस/प्रति बुकिंग किया जा सकेगा।
- (10) नगर पालिका परिषद्, देवरिया की सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 05.00 लिया जायेगा।
- (11) नगर पालिका परिषद्, देवरिया में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, देवरिया के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 के हिसाब से वसूल किया जायेगा।
- (12) नगर पालिका परिषद्, देवरिया सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।
- (13) नगर पालिका परिषद्, देवरिया सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों/नगर पालिका के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

- (14) नगर पालिका परिषद्, देवरिया सीमान्तर्गत 50 माइक्रान से ऊपर के प्लास्टिक, पालीथीन का गिलास, कप, प्लेट आदि में खाद्य का पेय चाय, काफी, शर्बत, कोल्ड ड्रिंक आदि सामग्री के बिक्री पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं पुनरावृत्ति पर रु0 2,000.00 देय होगा साथ ही साथ उपरोक्त सामानों के भण्डारण करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर जुर्माना रु0 15,000.00 किया जायेगा।
- (15) नगर पालिका परिषद्, देवरिया सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों आदि को तोड़ने क्षति करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति वर्ग मीटर।
- (16) नगर पालिका परिषद्, देवरिया सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों, नगर पालिका के स्वामित्व के भवनों, विद्युत पोलों, फुटपाथों, डिवाइडरों आदि पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार प्रदर्शन आदि करने पर किसी भी साइज का पोस्टर लगाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति पोस्टर, बॉस या लोहे का खम्भा गाड़कर होर्डिंग लगाने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रति वर्ग मीटर होगा। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कुड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6-क, 7, 12, और 13-क के अधीन अनुच्छेद 24-थ के अधीन नगर पालिका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित कपों, गिलास, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों, कैरी बैग आदि प्रतिषिद्ध किये गये हैं। यदि इसका प्रयोग करते हुए पाये जाने पर निम्नानुसार दण्ड प्रामिनामित सक्षम अधिकारी/गठित समिति में निहित होगा, विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं० (क)	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपयों में
1	2	3
		रु0
01	100 ग्राम तक	1,000.00
02	101 ग्राम-500 ग्राम	2,000.00
03	501 ग्राम-01 किलोग्राम	5,000.00
04	01 किलोग्राम-05 किलोग्राम	10,000.00
05	05 किलोग्राम से अधिक	25,000.00
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाना	25,000.00
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों,	1,000.00

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

- (17) नगर पालिका परिषद्, देवरिया द्वारा निर्मित विवाह घर, सार्वजनिक शौचालय, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क, तालाबों आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड़ पौधे, स्ट्रीट लाइटों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 4,000.00 प्रति अदद किया जायेगा।
- (18) नगर पालिका परिषद्, देवरिया द्वारा बनाये गये उप नियम शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पालिका परिषद्, देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

### दण्ड

“उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत यदि कोई भी व्यक्ति उप नियमों की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप विधि के पैरा 1 लगायत 17 तक में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।”

ह0 (अस्पष्ट),

अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद्, देवरिया।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स “जौहर एसोसिएट”, गुलजार-ए-अजमत चौक, मोहम्मद सईद खान, रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 31 मार्च, 2020 को नईम खान पुत्र श्री शिफात खान, निवासी इमली झूले वाली, तहसील सदर, जिला रामपुर, उ0प्र0 रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्रीमती शबिस्ता पत्नी सैय्यद खालिद, निवासी गुलजार-ए-अजमत, चौक, मोहम्मद सईद खान, तहसील सदर, जिला रामपुर शामिल हो गई हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री सैय्यद खालिद व श्रीमती शबिस्ता रह गये हैं।

सैय्यद खालिद,

पार्टनर,

फर्म मेसर्स “जौहर एसोसिएट”,

गुलजार-ए-अजमत चौक,

मोहम्मद सईद खान,

रामपुर (यू0पी0)।

### NOTICE

In the matter of Haji Mohd. Ali, Mohd. Ishaq, Regd. Office 398, Third Lane, Nishatganj, Lucknow.

Partners of Haji Mohd. Ali, Mohd. Ishaq.

1. Mohd. Aslam Ahmad S/o Late Mohd. Ishaq Ahmad aged about 67.

2. Faisal Aslam S/o Late Mohd. Aslam Ahmad aged about 37.

3. Zeeshan Aslam S/o Late Mohd. Aslam Ahmad aged about 28.

4. Suhail Akram S/o Late Akram Ahmad aged about 22.

5. Shoaib Akram S/o Late Akram Ahmad aged about 18.

All the residents of 398, 3<sup>rd</sup> Lane, Nishatganj, Lucknow decided to include the name of Shoaib Akram S/o Late Akram Ahmad, R/o 398, 3<sup>rd</sup> Lane, Nishatganj, Lucknow as full fledged partner with effect from 1st August, 2019 as earlier he was the partner under the guardianship of her mother Tasneem Kausar and attained majority on 31<sup>st</sup> July, 2019 so all the partners of the firm accepted him full

fledge partner of the firm M/s. Haji Mohd. Ali, Mohd. Ishaq with effect 1<sup>st</sup> August, 2019.

HAJI MOHD. ALI,

MOHD. ISHAQ,

Partener,

HDLK 1901082.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 लोकेश कन्स्ट्रक्शन भाँटी कला ढाँढर पट्टी, प्रतापगढ़ में श्रीमती अनुपमा वर्मा एवं जितेन्द्र कुमार वर्मा साझेदार थे। श्री संत राम वर्मा पुत्र श्री महाबल वर्मा, निवासी एल0 आई0 जी0 95, साकेतपुर कालोनी देवकाली, फैजाबाद, दिनांक 22 जून, 2020 को फर्म में तीसरे साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं।

अनुपमा वर्मा,

साझेदार,

मे0 लोकेश कन्स्ट्रक्शन,

भाँटी कला ढाँढर पट्टी, प्रतापगढ़।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्षमा तिवारी पुत्री जटा शंकर तिवारी और क्षमा द्विवेदी पत्नी पवन कुमार द्विवेदी, निवासिनी-22, ए/2डी, चक मुन्डेरा, प्रयागराज एक ही व्यक्ति हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्षमा तिवारी का ही आधार कार्ड संख्या 392704015367 एवं पैन कार्ड संख्या AOEPD6647J क्षमा द्विवेदी के नाम से निर्गत हुआ है। उक्त कारण से ही क्षमा

तिवारी का बैंक में खाता क्षमा द्विवेदी के नाम से संचालित हैं अतः क्षमा द्विवेदी एवं क्षमा तिवारी एक ही व्यक्ति हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अब क्षमा तिवारी के नाम से ही जानी जायेंगी।

क्षमा तिवारी,

निवासिनी-22, ए/2डी,

चक मुन्डेरा,

प्रयागराज-211011

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 टेक्नो इन्डस्ट्रीज 67/23/41-जे, रामानन्द नगर, अल्लापुर, प्रयागराज में साझेदार छवि विवेक शर्मा, दिनांक 13 मार्च, 2020 को फर्म से रिटायर हो चुकी है। दिनांक 13 मार्च, 2020 से इन्हें फर्म के लाभ-हानि से कोई वास्ता या सरोकार नहीं है।

रमा शंकर शर्मा,

(साझेदार),

मे0 टेक्नो इन्डस्ट्रीज,

67/23/41-जे, रामानन्द नगर,

अल्लापुर, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में राम लाल सुन्दर लाल, कन्नौज में विनीत कुमार गुप्ता, पुनीत कुमार गुप्ता एवं सुन्दर लाल थे। दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को सुन्दर लाल की मृत्यु हो गयी, अब फर्म में विनीत कुमार गुप्ता एवं पुनीत कुमार गुप्ता है। फर्म में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

पुनीत कुमार गुप्ता।